

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम० के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 228-दो/2007 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.12.2006 पारित द्वारा - अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण क्रमांक 545 अ-19/05-06 निगरानी

- 1- मुन्नीलाल पुत्र अनन्दी अहिरवार
- 2- छोटेलाल पुत्र अनन्दी अहिरवार
- 3- वृजलाल पुत्र अनन्दी अहिरवार
- 4- छक्कीलाल पुत्र तिजई

सभी ग्राम इटायली तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- रामचरण पुत्र घासीराम चमार
- 2- बलराम पुत्र तिजू धोवी
- 3- मन्जू (मृतक) वारिसान
गोरेलाल पुत्र स्व. मंजू सभी ग्राम
इटायली तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री जे.एल.गौड़)

आ दे श

(आज दिनांक 5-11-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 545 अ-19/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2006 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि नायव तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2002 से ग्राम इटायली के 26 भूमिहीनों को भूमि का आवंटन किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण ने

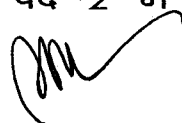


अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष अपील क्रमांक 97/2002-03 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 24-5-2006 से आंशिकरूप से अपील स्वीकार कर मनोहर पुत्र पर्वत कुम्हार के हित में भूमि खसरा नंबर 13 रकबा 0.825 हैक्टर का बंटन निरस्त किया गया तथा शेष 25 भूमिहीनों का बंटन यथावत् रखा गया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के यहां निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 545 अ-19/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2006 से निगरानी स्वीकार की गई तथा तहसीलदार पलेरा को निर्देश दिये गये कि अनावेदकगणों को प्राप्त पट्टे की भूमि का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाय एवं तरमीम कर विधिवत नक्शे तैयार किये जाय तथा आवेदकगण की पट्टे की भूमि जिन लोगों को पुनः बंटन में दी गई है उनका बंटन निरस्त किया जाय तथा पात्रतानुसार उन्हें अन्य भूमि देने की कार्यवाही की जावे। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को बहस में सुना तथा अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 20.12.2006 के पद-2 में निष्कर्ष दिया है कि :-

K



- तहसीलदार पलेरा ने दि. 28.3.2002 को आदेश पत्रिका में यह उल्लेख किया है कि ग्राम इटायली में भूमिहीन अनु.जाति, अनु०जनजाति के व्यक्तियों को भूमि का बंटन किया जाना है। दि. 28-3-02 की आदेश पत्रिका में उदघोषणा जारी हो और 9-4-2002 की पेशी अंकित की गई है जो कि मात्र ग्यारह दिवस की पेशी देकर उदघोषणा का आदेश दिया गया है, अभिलेख में उदघोषणा पृष्ठ-11 पर है जांच प्रतिवेदन दि. 16-5-02 को जांच प्रतिवेदन में ही नायब तहसीलदार पलेरा ने पट्टे जारी किये, अनुमोदन के लिये तहसीलदार पलेरा को भेजा। तहसीलदार पलेरा ने अनु०अधिकारी पलेरा को प्रकरण अनुमोदन के लिये भेजा। अनुविभागीय अधिकारी पलेरा ने दि. 22-6-02 को यह अंकित कर नस्ती वापिस की कि, राजस्व विभाग के ज्ञापन दि. 2-3-02 के अनुसार बंटन कार्यवाहीपूर्ण करें, जिससे स्पष्ट है कि अनु. अधिकारी ने अनुमोदन नहीं किया, उसके बाबजूद भी बंटन कर दिया गया। *

विचार योग्य है कि नायब तहसीलदार के उक्त बंटन आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी पलेरा के समक्ष अपील क्रमांक 97/2002-03 प्रस्तुत हुई, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भूमि बंटन नियम विरुद्ध होने का तथ्य उजागर होने एवं स्वयं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बंटन का अनुमोदन नहीं देने का तथ्य आ चुका था। इसी प्रकार अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा की गई उपरोक्त विवेचना अनुसार उनके अभिज्ञान में भी भूमि बंटन अनियमित होने का तथ्य आ चुका था, फिर भी उन्होंने नायब तहसीलदार पलेरा के आदेश दिनांक 16-5-2002 को आंशिक सँशोधन उपरांत स्थिर रखा है, जबकि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को आदेश दिनांक 20.12.2006 पारित करते समय उनके द्वारा उपरोक्तानुसार निकाये गये निष्कर्ष को ध्यान में रखकर नायब तहसीलदार द्वारा

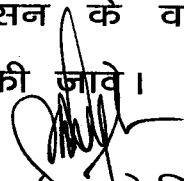
f



भूमि बन्टन में की गई अनियमिततायें उजागर होने पर नायव तहसीलदार के बन्टन आदेश दिनांक 16-5-02 को अंशतः निरस्त न करके संपूर्ण आदेश को निरस्त करना चाहिये था, जब भूमि बन्टन कार्यवाही प्रारंभ से ही नियम व प्रक्रिया के विरुद्ध है तब नायव तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2002 को पूर्णतः निरस्ती योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी के तथ्य आवेदकगण के हित में न होने से निगरानी अमान्य की जाती है। प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 545 अ-19/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2006, अनुविभागीय अधिकारी, जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 97/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 24-5-2006 तथा नायव तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 10 अ-19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2002 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम आवंटित की गई समस्त भूमि को भूमि बन्टन के पूर्व की स्थिति में शासकीय अभिलेख में दर्ज कराया जावे। तदुपरांत नायव तहसीलदार के प्र.क. 10 अ-19/ 2001-02 का स्वस्तर से परीक्षण कर भूमिहीनों की पात्रता का निर्धारण करते हुये शासन के वर्तमान निर्देशों के प्रकाश में पुनः बन्टन की कार्यवाही की जावे।

र
रिस्ट



(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर